The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 4 | Issue 5 | May 2026
ISSN: 2583-973X (Online), SJIF IF: 5.6
Website: www.theacademic.in

उत्तराखंड के हिमालयी दर्रों के माध्यम से भारत-तिब्बत (चीन) सीमा व्यापार: ऐतिहासिक विकास, सामाजिक-आर्थिक आयाम और समकालीन भू-राजनीतिक विश्लेषण

डॉ. पंकज पाण्डेय, डॉ. राकेश मोहन नौटियाल, डॉ. अमित चमोली

[1] सह आचार्य, इतिहास विभाग, शहीद दुर्गामल राजकीय स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय, डोईवाला, देहरादून

[1] सहायक आचार्य, इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय, कमान्द, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड. ईमेल : history.rakeshnautiyal@gmail.com

[1] सहायक आचार्य (विजिटिंग), इतिहास विभाग, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविध्यालय, जयपुर राजस्थान.

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.20699309

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 21-05-2026

Published: 10-06-2026

Keywords:

भारत, तिब्बत, विदेश नीति, नेपाल, लिपुलेख, चीन, भारत-चीन सम्बद्ध

ABSTRACT

प्रस्तुत दस्तावेज़ उत्तराखंड के हिमालयी दर्रों, विशेष रूप से लिपुलेख, माणा और नीति, के माध्यम से भारत-तिब्बत (चीन) सीमा व्यापार के ऐतिहासिक विकास और समकालीन सामरिक महत्व का विस्तृत विश्लेषण करता है। ऐतिहासिक रूप से ये दर्रे न केवल रेशम मार्ग का हिस्सा थे, बल्कि हिमालयी समाजों, विशेषकर भोटिया जनजाति की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना का आधार भी रहे हैं। 1954 के समझौते के माध्यम से विकसित हुआ यह व्यापार 1962 के युद्ध के बाद पूर्णतः बाधित हो गया, जिससे सीमावर्ती समुदायों को विस्थापन और सांस्कृतिक संकट का सामना करना पड़ा। हालांकि 1992 से व्यापार की सीमित बहाली हुई है, किंतु वर्तमान में यह क्षेत्र लिपुलेख दर्रे को लेकर भारत, नेपाल और चीन के मध्य एक जटिल त्रिकोणीय भू-राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बन गया है। भारत सरकार अब 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से इन सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के बीच संतुलन साधने का प्रयास कर रही है, जबकि अगस्त 2025 के हालिया कूटनीतिक 'रिसेट' ने व्यापार और कैलाश मानसरोवर यात्रा की पुनः बहाली की नई संभावनाएं जगाई हैं।

शोधपत्र का मूल पाठ

हिमालय की गगनचुंबी पर्वत-श्रृंखलाएँ प्राचीन काल से केवल भारत की प्राकृतिक अथवा भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण नहीं करती रहीं, बल्कि वे सांस्कृतिक चेतना, आर्थिक संपर्क और सभ्यतागत अंतःक्रिया की एक सक्रिय धुरी के रूप में विकसित हुईं। उत्तराखंड क्षेत्र में स्थित उच्च पर्वतीय दर्रे—जिन्हें स्थानीय परंपरा में 'ला' अथवा 'धुरा' कहा जाता है—ऐतिहासिक रूप से भारत और तिब्बत के मध्य व्यापारिक तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान के प्रमुख मार्ग रहे हैं[i]। इन दर्रों के माध्यम से संचालित सीमा व्यापार केवल वाणिज्यिक गतिविधि तक सीमित नहीं था, बल्कि यह हिमालयी समाजों की आजीविका, उनकी सामाजिक संरचना तथा विशिष्ट सांस्कृतिक विन्यास का आधार भी बना[ii] । ऐतिहासिक साक्ष्य यह भी संकेत करते हैं कि ये पर्वतीय व्यापारिक मार्ग व्यापक रेशम मार्ग से संबद्ध थे, जिसके परिणामस्वरूप ऊन, नमक और बोरेक्स जैसी वस्तुओं के साथ-साथ विचारों, दार्शनिक अवधारणाओं तथा धार्मिक परंपराओं का भी निर्बाध प्रवाह संभव हुआ[iii] । इस प्रकार, हिमालयी दर्रे भारत-तिब्बत संबंधों के साथ-साथ एशियाई सभ्यताओं के पारस्परिक संवाद के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरते हैं।

ऐतिहासिक विकास और सभ्यतागत संबंधों की नींव

भारत और चीन के मध्य संबंधों की ऐतिहासिक जड़ें अत्यंत प्राचीन हैं, जिनका विस्तार आधुनिक राष्ट्र–राज्य की अवधारणा से बहुत पहले तक जाता है। उपलब्ध ऐतिहासिक और भाषाई साक्ष्य संकेत करते हैं कि लगभग 1500–1000 ईसा पूर्व के कालखंड में चीन की सांग–झोउ सभ्यता और भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के मध्य वैचारिक तथा भाषिक संपर्क के प्रारंभिक रूप विकसित हो चुके थे[iv] । ईसा की प्रथम से तृतीय शताब्दी के मध्य, बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ यह संपर्क और अधिक सुदृढ़ हुआ, जब चीनी बौद्ध तीर्थयात्री एवं विद्वान—विशेषतः फा श्यान और ह्वेन त्सांग—दुर्गम हिमालयी दर्रों को पार करते हुए भारत आए और भारतीय धार्मिक-दार्शनिक परंपराओं का अध्ययन किया [v]।

उत्तराखंड के कुमाऊँ और गढ़वाल क्षेत्रों में स्थित लिपुलेख, नीति तथा माणा जैसे उच्च पर्वतीय दर्रे न केवल इन बौद्ध यात्रियों के लिए, बल्कि भारत-तिब्बत व्यापार में संलग्न व्यापारियों के लिए भी जीवनरेखा के समान थे [vi]। मध्यकालीन एवं प्रारंभिक आधुनिक काल में इन व्यापारिक मार्गों पर कुमाऊँ के चंद शासकों तथा गढ़वाल के पंवार वंश का प्रभावी नियंत्रण रहा, जिसके माध्यम से नमक, ऊन, बोरेक्स और अनाज जैसी वस्तुओं का नियमित विनिमय होता था[vii] ।

उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में 1814–1816 के आंग्ल-नेपाल युद्ध (गोरखा युद्ध) के पश्चात हस्ताक्षरित सुगौली की संधि ने इस हिमालयी क्षेत्र की राजनीतिक और भौगोलिक संरचना को निर्णायक रूप से प्रभावित किया[viii] । इस संधि के अंतर्गत महाकाली (काली) नदी को ब्रिटिश भारत और नेपाल के मध्य सीमा के रूप में स्वीकार किया गया, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव लिपुलेख दर्रे की स्थिति और उससे जुड़े सीमा प्रश्नों पर आज तक देखा जा सकता है[ix] ।

ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भारत-तिब्बत व्यापार को संस्थागत रूप देने के प्रयास किए गए, क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन तिब्बत को एक बफर स्टेट तथा संभावित वाणिज्यिक बाजार के रूप में देखता था। *Almora Gazetteer* (1911) के अभिलेख इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि उस समय भी काली नदी का उद्गम लिपुलेख दर्रे के समीप माना जाता था और यह क्षेत्र भारत-तिब्बत व्यापार का एक सक्रिय केंद्र बना हुआ था [x]।

1954 का समझौता: आधुनिक सीमा व्यापार का स्वर्णिम चरण

स्वतंत्र भारत और जनवादी गणराज्य चीन के मध्य व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को औपचारिक और संस्थागत स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से 29 अप्रैल 1954 को *"तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार और संसर्ग पर समझौता"* संपन्न हुआ [xi]। यह समझौता भारत-चीन संबंधों के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ, क्योंकि इसी के माध्यम से पंचशील—अर्थात् शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पाँच सिद्धांत—को अंतरराष्ट्रीय संबंधों की वैचारिक आधारशिला के रूप में प्रतिष्ठित किया गया[xii] ।

इस समझौते के अंतर्गत उत्तराखंड क्षेत्र के छह प्रमुख हिमालयी दर्रों को व्यापार और तीर्थयात्रा के लिए अधिकृत किया गया, जिससे भारत-तिब्बत सीमा व्यापार को एक वैधानिक और संगठित ढाँचा प्राप्त हुआ [xiii]। इन अधिकृत दर्रों के माध्यम से ऊन, नमक, बोरेक्स तथा हस्तशिल्प वस्तुओं का नियमित आदान-प्रदान संभव हुआ, जिसने सीमावर्ती हिमालयी समुदायों की आर्थिक स्थिरता और आजीविका को सुदृढ़ किया [xiv]।

इसके साथ ही, इस सीमा व्यापार का प्रभाव केवल पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कलिम्पोंग, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी जैसे मैदानी व्यापारिक केंद्र भी इससे प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए। ये नगर भारत-तिब्बत और भारत-चीन व्यापारिक नेटवर्क के प्रमुख नोड्स के रूप में उभरे और आधुनिक काल में उनके नगरीय तथा आर्थिक विकास को गति मिली[xv] । इस प्रकार, 1954 का समझौता न केवल द्विपक्षीय कूटनीतिक सौहार्द का प्रतीक था, बल्कि इसने हिमालयी सीमा व्यापार को उसके आधुनिक "स्वर्णिम काल" में प्रवेश कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

तालिका 1: 1994 के समझौते के तहत उत्तराखंड के प्रमुख व्यापारिक दर्रे

दर्रे का नाम	जिला (भारत)	ऊँचाई (लगभग)	व्यापारिक और धार्मिक महत्व
लिपुलेख दर्रा	पिथौरागढ़	5334 मीटर	कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्राचीन मार्ग; ताकलाकोट (तिब्बत) से जुड़ाव

माणा दर्रा	चमोली	5610 मीटर	बद्रीनाथ के उत्तर में स्थित; पांडवों के स्वर्गारोहण का पथ माना जाता है
नीति दर्रा	चमोली	5068 मीटर	नमक, ऊन और सुहागा व्यापार का ऐतिहासिक गलियारा
मंशा धुरा	पिथौरागढ़	5494 मीटर	कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला दर्रा
मुलिंग ला	उत्तरकाशी	5669 मीटर	गंगोत्री के उत्तर में महान हिमालय में स्थित सामरिक मार्ग

इस कालखंड में भारत–तिब्बत सीमा व्यापार की प्रकृति मुख्यतः वस्तु-विनिमय प्रणाली (Barter System) पर आधारित थी, जिसमें मुद्रा की भूमिका अत्यंत सीमित रही [xvi]। भारतीय व्यापारी गेहूँ, चावल, चीनी, गुड़, तंबाकू तथा सूती वस्त्र जैसी कृषि एवं उपभोक्ता वस्तुएँ तिब्बत ले जाते थे और इसके प्रतिफलस्वरूप ऊन, नमक, सुहागा (बोरेक्स), कीमती पत्थर तथा विभिन्न पशु-उत्पाद भारत लाते थे[xvii]। इस प्रकार का विनिमय केवल आर्थिक लेन-देन तक सीमित नहीं था, बल्कि यह हिमालयी समाजों के मध्य पारस्परिक निर्भरता और सहयोग की परंपरा को भी सुदृढ़ करता था।

इसके अतिरिक्त, यह व्यापारिक व्यवस्था एक व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक चक्र का अभिन्न अंग थी, जिसमें व्यापारिक यात्राएँ स्थानीय पर्वों, मेलों तथा धार्मिक अनुष्ठानों से गहराई से जुड़ी हुई थीं [xviii]। अनेक अवसरों पर व्यापारिक कारवाँ वार्षिक उत्सवों और तीर्थ यात्राओं के साथ संचालित होते थे, जिससे आर्थिक गतिविधियों के साथ-साथ सांस्कृतिक संपर्क और सामाजिक अंतःक्रिया भी सघन होती गई [xix]। इस संदर्भ में भारत-तिब्बत सीमा व्यापार को केवल वाणिज्यिक प्रक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि हिमालयी क्षेत्रों की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में समझा जा सकता है।

<u>1962 का युद्ध और भारत–चीन व्यापारिक संबंधों का विखंडन</u>

1959 के तिब्बती विद्रोह तथा चतुर्दश दलाई लामा को भारत द्वारा शरण प्रदान किए जाने के पश्चात भारत और जनवादी गणराज्य चीन के संबंधों में तीव्र तनाव उत्पन्न हुआ, जिसने द्विपक्षीय विश्वास और सहयोग की पूर्ववर्ती संरचना को गंभीर रूप से प्रभावित किया [xx]। यह तनाव अक्टूबर–नवंबर 1962 में सशस्त्र सीमा संघर्ष में परिवर्तित हो गया, जिसके परिणामस्वरूप सदियों से विद्यमान भारत–तिब्बत व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संपर्क लगभग पूर्णतः समाप्त हो गए[xxi]। युद्धोत्तर परिस्थितियों में उत्तराखंड क्षेत्र के सभी प्रमुख हिमालयी दर्रों को सील कर दिया

गया और सीमावर्ती क्षेत्रों को उच्च-संवेदनशील सैन्य क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया गया, जिससे पारंपरिक सीमा व्यापार पर पूर्ण विराम लग गया [xxii]।

1962 के युद्ध का सर्वाधिक गहन सामाजिक-आर्थिक प्रभाव उत्तराखंड की भोटिया जनजाति पर पड़ा, जिनकी पारंपरिक आजीविका सीमा व्यापार और ऊन-आधारित अर्थव्यवस्था पर आश्रित थी[xxiii]। सीमा बंद होने के परिणामस्वरूप तिब्बत से कच्ची ऊन की आपूर्ति रुक गई, जिससे भोटिया समुदाय की पारंपरिक आर्थिक संरचना तीव्र संकट में पड़ गई [xxiv]। इसके अतिरिक्त, सामरिक कारणों से उत्तरकाशी जिले की नेलांग और जादुंग जैसी सीमावर्ती घाटियों को खाली करवा लिया गया और वहां निवासरत समुदायों को निचले क्षेत्रों में पुनर्वासित किया गया[xxv]।

इस जबरन विस्थापन का प्रभाव केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने भोटिया समुदाय की सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों तथा सामाजिक संरचना को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया[xxvi]। सदियों से हिमालयी पर्यावरण के साथ विकसित हुई उनकी जीवन-पद्धति, पशुपालन तकनीकें और सीमा-पार सांस्कृतिक संपर्क अचानक समाप्त हो गए, जिससे यह समुदाय दीर्घकालिक सामाजिक और सांस्कृतिक असुरक्षा की स्थिति में पहुँच गया। इस प्रकार, 1962 का युद्ध न केवल भारत–चीन संबंधों में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ, बल्कि इसने उत्तराखंड के सीमावर्ती समाजों के ऐतिहासिक विकास-पथ को भी गहरे स्तर पर बाधित किया।

<u>सामाजिक-आर्थिक आयाम: भोटिया समुदाय का रूपांतरण और लचीलापन</u>

उत्तराखंड की भोटिया जनजाति एक अर्ध-खानाबदोश हिमालयी समुदाय रही है, जो ऐतिहासिक रूप से पार-हिमालयी व्यापार की निरंतरता और संचालन में केंद्रीय भूमिका निभाती आई है[xxvii]। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और मौसमी प्रवासन के बावजूद, इस समुदाय ने सदियों तक भारत-तिब्बत सीमा क्षेत्र में आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संपर्कों को जीवित रखा। भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक परंपराओं और व्यापारिक मार्गों के आधार पर भोटिया समुदाय को कई उपसमूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है[xxviii]।

चमोली जनपद की माणा और नीति घाटियों में निवास करने वाले **मारछा और तोलछा भोटिया** पारंपरिक रूप से तिब्बत के साथ नमक-ऊन व्यापार से जुड़े रहे हैं[xxix]। इसी प्रकार, उत्तरकाशी जिले की नेलांग घाटी से संबद्ध **जाड भोटिया**, 1962 के युद्ध के पश्चात सुरक्षा कारणों से विस्थापित होकर बागोरी एवं समीपवर्ती क्षेत्रों में पुनर्वासित हुए, जिससे उनकी पारंपरिक जीवन-पद्धति में मूलभूत परिवर्तन आया [xxx]। पिथौरागढ़ जिले की व्यास, दारमा और जोहार घाटियों में केंद्रित **शौका और जोहारी भोटिया** समूह लंबे समय तक सीमा व्यापार, पशुपालन और मौसमी प्रवासन पर आधारित अर्थव्यवस्था का संचालन करते रहे हैं[xxxi]।

भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तराखंड में भोटिया जनजाति की कुल जनसंख्या 39,106 दर्ज की गई थी [xxxii]। 1962 के भारत-चीन युद्ध के पश्चात पारंपरिक व्यापार मार्गों के बंद हो जाने से उत्पन्न आर्थिक संकट को देखते हुए, इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ताकि आरक्षण, कल्याणकारी योजनाओं और विशेष विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उनके सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास को सुनिश्चित किया जा सके[xxxiii]। यद्यपि इस नीति से शिक्षा और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हुए, तथापि पारंपरिक व्यापार-आधारित जीवन-शैली से आधुनिक आजीविका की ओर यह संक्रमण भोटिया समाज के लिए एक जटिल और दीर्घकालिक प्रक्रिया सिद्ध हुआ।

पारंपरिक व्यापारिक वस्तुओं का विवरण

ऐतिहासिक रूप से व्यापार का स्वरूप द्विपक्षीय और बहुपक्षीय था। भारतीय व्यापारी अक्सर तिब्बती नमक को नेपाल ले जाते थे और वहां से अनाज और जड़ी-बूटियाँ लेकर भारत लौटते थे।

तालिका 2: उत्तराखंड-तिब्बत व्यापार की प्रमुख वस्तुएं

श्रेणी	भारत से तिब्बत को निर्यात	तिब्बत से भारत को आयात
खाद्य सामग्री	चावल, गेहूं, चीनी, गुड़, मिश्री, चाय, तंबाकू	नमक, मक्खन, कीमती जड़ी-बूटियाँ
वस्त्र और हस्तशिल्प	सूती वस्त्र, रेशमी कपड़े, बर्तन (पीतल/तांबा)	कच्ची ऊन, पश्मीना, कालीन, ऊनी कोट, जूते
पशु और उत्पाद	बकरी, भेड़, घोड़े, खच्चर	याक की पूंछ, पशु खाल, कस्तूरी
विविध	माचिस, साबुन, खिलौने, वनस्पति तेल	सुहागा (Borax), सोना (गोल्ड डस्ट), कीमती पत्थर

समकालीन सामाजिक परिवर्तन: आजीविका, शिक्षा और सांस्कृतिक संकट

पार-हिमालयी व्यापार के बंद हो जाने के पश्चात भोटिया समुदाय की सामाजिक-आर्थिक संरचना में उल्लेखनीय परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। पारंपरिक व्यापार और पशुपालन आधारित आजीविका के क्षय के बाद इस समुदाय ने शिक्षा, सरकारी सेवाओं तथा आधुनिक व्यावसायिक गतिविधियों को वैकल्पिक आजीविका के रूप में अपनाया

है[xxxiv]। वर्तमान परिदृश्य में भोटिया समुदाय के अनेक सदस्य प्रशासनिक सेवाओं, सशस्त्र बलों तथा निजी व्यापारिक उद्यमों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं, जो इस समुदाय की अनुकूलन क्षमता और सामाजिक लचीलेपन को रेखांकित करता है [xxxv]।

विशेष रूप से जाद भोटिया महिलाओं पर केंद्रित अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि समुदाय के भीतर लैंगिक भूमिका में भी परिवर्तन हो रहा है। उपलब्ध शोध के अनुसार, लगभग 56 प्रतिशत जाड भोटिया महिलाएँ वर्तमान में स्वरोजगार, पारंपरिक हस्तशिल्प तथा लघु उद्यमों से जुड़ी हुई हैं, जबकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है [xxxvi]। यह परिवर्तन न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में संकेत करता है, बल्कि सामाजिक संरचना में महिलाओं की भूमिका के पुनर्परिभाषण को भी दर्शाता है।

इसके बावजूद, तीव्र आधुनिकीकरण, शहरी प्रवास और औपचारिक शिक्षा की प्रधानता के कारण भोटिया समुदाय की पारंपरिक बोलियों, लोक-स्मृतियों तथा सांस्कृतिक अनुष्ठानों का क्षरण एक गंभीर चिंता के रूप में उभर रहा है[xxxvii]। मौसमी प्रवासन, सामूहिक उत्सवों और सीमा-व्यापार से जुड़े सांस्कृतिक अभ्यासों के समाप्त हो जाने से अंतर-पीढ़ीगत सांस्कृतिक हस्तांतरण बाधित हुआ है। इस संदर्भ में भोटिया समाज का समकालीन रूपांतरण एक द्वंद्वात्मक स्थिति को प्रतिबिंबित करता है, जहाँ एक ओर सामाजिक-आर्थिक उन्नति के नए अवसर उपलब्ध हुए हैं, वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियाँ निरंतर संकटग्रस्त होती जा रही हैं।

<u>व्यापार की बहाली: 1992 से 2019 तक का विश्लेषण</u>

लगभग तीन दशकों तक भारत–चीन सीमा व्यापार के पूर्णतः अवरुद्ध रहने के पश्चात, 1991 में चीनी प्रधानमंत्री ली पेंग की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सीमा व्यापार को पुनः प्रारंभ करने पर सहमति बनी, जिसे द्विपक्षीय विश्वास-निर्माण उपाय (Confidence Building Measure) के रूप में देखा गया [xxxviii]। इस सहमति के परिणामस्वरूप 1992 में उत्तराखंड स्थित लिपुलेख दर्रे को सीमित सीमा व्यापार के लिए पुनः खोला गया, जो 1962 के युद्ध के बाद पुनः सक्रिय होने वाला पहला पार-हिमालयी व्यापारिक मार्ग था[xxxix]। इसके पश्चात 1993 में हिमाचल प्रदेश के शिपकी ला दर्रे तथा 2006 में सिक्किम के नाथू ला दर्रे को व्यापार के लिए खोले जाने से भारत–तिब्बत सीमा व्यापार का एक नियंत्रित पुनरुद्धार संभव हुआ[xl]।

हालाँकि, यह व्यापारिक बहाली अपने स्वरूप में अत्यंत सीमित, मौसमी और कठोर रूप से विनियमित रही। सीमा व्यापार केवल जून से सितंबर के मध्य संचालित किया जाता है, जो हिमालयी भौगोलिक परिस्थितियों और मौसम पर निर्भर करता है, तथा इसमें भाग लेने वाले व्यापारियों को विशेष परमिट और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होता है[xli]। उत्तराखंड के व्यापारियों के लिए तिब्बत के ताकलाकोट (पुरांग) में एक निर्दिष्ट व्यापारिक मंडी

(trade mart) की व्यवस्था की गई है, जहाँ भारतीय व्यापारी अपने उत्पादों का विक्रय करते हैं और तिब्बती ऊन, नमक तथा अन्य सीमित वस्तुओं की खरीद करते हैं [xlii]।

इसके बावजूद, शोध अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि यह पुनर्जीवित व्यापार 1962-पूर्व काल के व्यापक और सामुदायिक व्यापार नेटवर्क का स्थान नहीं ले सका। सीमित वस्तुओं की सूची, कठोर नियामक ढाँचा और परिवहन संबंधी बाधाएँ इस व्यापार को मुख्यतः प्रतीकात्मक और कूटनीतिक महत्व तक सीमित रखती हैं[xliii]। इस प्रकार, 1992 से 2019 के बीच सीमा व्यापार की बहाली को एक पूर्ण आर्थिक पुनरुद्धार के बजाय भारत–चीन संबंधों में सावधानीपूर्ण सहयोग और रणनीतिक संतुलन के प्रयास के रूप में समझा जा सकता है।

व्यापारिक मात्रा और चुनौतियां

तथ्यों के अनुसार, उत्तराखंड के माध्यम से होने वाला सीमा व्यापार राष्ट्रीय स्तर के व्यापार की तुलना में नगण्य है, लेकिन स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए इसका महत्व अधिक है।

तालिका 3: लिपुलेख दर्रे के माध्यम से व्यापार के आंकड़े (2014-2016)

वर्ष	कुल व्यापार मूल्य (करोड़ ₹)	भारतीय निर्यात (₹)	चीनी/तिब्बती आयात (₹)
2014	3.06	1.91 करोड़	2.14 करोड़
2015	4.36	1.60 करोड़	2.76 करोड़
2016	5.86 (केवल निर्यात)	5.86 करोड़	अत्यधिक गिरावट दर्ज

व्यापारियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिनमें बुनियादी ढांचे की कमी, संचार सुविधाओं का अभाव और विनिमय दरों की समस्या प्रमुख है I चीनी अधिकारियों द्वारा तंबाकू, गुड़ और मिश्री जैसे पारंपरिक निर्यात उत्पादों पर लगाए गए प्रतिबंधों ने व्यापार की लाभप्रदता को कम कर दिया हैI इसके अलावा, ताकलाकोट मंडी में आधुनिक सुविधाओं जैसे कोल्ड स्टोरेज और बैंकिंग सेवाओं की कमी व्यापारियों के लिए एक बाधा बनी हुई है।

समकालीन भू-राजनीतिक विश्लेषण: लिपुलेख दर्रा और त्रिकोणीय कूटनीतिक संघर्ष

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लिपुलेख दर्रा केवल भारत और चीन के मध्य सामरिक एवं व्यापारिक संपर्क का मार्ग भर नहीं रह गया है, बल्कि यह भारत–नेपाल संबंधों में भी एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक विवाद का केंद्र बनकर उभरा है[xliv]। यह दर्रा भारत, चीन और नेपाल के त्रिजंक्शन (trijunction) क्षेत्र के निकट स्थित है, जिसके कारण इसकी भू-राजनीतिक संवेदनशीलता अत्यधिक बढ़ जाती है[xlv]।

ऐतिहासिक रूप से लिपुलेख दर्रे का उपयोग भारत–तिब्बत व्यापार तथा कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्रा के लिए होता रहा है, किंतु समकालीन काल में सीमाओं के सटीक निर्धारण, औपनिवेशिक संधियों की भिन्न व्याख्याओं तथा आधुनिक राष्ट्र–राज्य की संप्रभुता संबंधी अवधारणाओं ने इसे एक विवादास्पद भू-स्थान में परिवर्तित कर दिया है [xlvi]। नेपाल द्वारा काली नदी के उद्गम को लेकर प्रस्तुत दावों और भारत द्वारा ऐतिहासिक प्रशासनिक नियंत्रण के तर्कों ने इस क्षेत्र को त्रिपक्षीय कूटनीतिक विमर्श का विषय बना दिया है[xlvii]।

चीन के लिए लिपुलेख दर्रा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सुरक्षा और सीमावर्ती स्थिरता से जुड़ा हुआ है, जबकि भारत के लिए यह सामरिक संपर्क, तीर्थयात्रा तथा सीमा प्रबंधन का महत्वपूर्ण बिंदु है। नेपाल की दृष्टि में यह दर्रा राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ा प्रश्न बन गया है[xlviii]। इस प्रकार, लिपुलेख दर्रा समकालीन दक्षिण एशियाई भू-राजनीति में केवल एक पर्वतीय मार्ग न होकर, ऐतिहासिक स्मृतियों, कूटनीतिक दावों और सामरिक हितों के अंतर्संघर्ष का प्रतीक बन गया है।

<u>भारत–नेपाल सीमा विवाद: कालापानी–लिपुलेख–लिम्पियाधुरा प्रश्न</u>

भारत–नेपाल सीमा विवाद का केंद्र लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र हैं, जिन्हें नेपाल सरकार अपने संप्रभु क्षेत्र का अभिन्न अंग मानती है[xlix]। नेपाल का यह दावा मुख्यतः 1816 की सुगौली संधि पर आधारित है, जिसके अनुसार काली नदी के पूर्व में स्थित समस्त भू-भाग नेपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है[l]। नेपाल की आधिकारिक व्याख्या के अनुसार काली नदी का वास्तविक उद्गम लिम्पियाधुरा क्षेत्र से होता है, और इस आधार पर लिपुलेख तथा कालापानी क्षेत्र नेपाल की सीमा के भीतर आते हैं[li]।

इसके विपरीत, भारत का आधिकारिक पक्ष यह है कि काली नदी का उद्गम कालापानी के समीप स्थित जलधारा से माना जाना चाहिए और यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से ब्रिटिश काल से भारत के प्रशासनिक नियंत्रण में रहा है[lii]। भारत का यह भी तर्क है कि स्वतंत्रता के पश्चात इस क्षेत्र में भारतीय प्रशासनिक, सैन्य और नागरिक उपस्थिति निरंतर बनी रही है, जो इसके प्रभावी नियंत्रण (effective control) को प्रमाणित करती है[liii]।

यह विवाद 2020 में उस समय और अधिक तीव्र हो गया, जब भारत द्वारा धारचूला से लिपुलेख तक एक रणनीतिक सड़क का उद्घाटन किया गया। नेपाल सरकार ने इस कदम पर तीव्र आपत्ति व्यक्त की और इसे अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन बताया[liv]। इसके पश्चात नेपाल ने अपने संविधान में संशोधन करते हुए एक नया आधिकारिक राजनीतिक मानचित्र जारी किया, जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल के भू-भाग के रूप में दर्शाया गया[lv]।

इस सीमा विवाद के परिणामस्वरूप भारत और नेपाल के मध्य ऐतिहासिक रूप से प्रचलित "रोटी–बेटी" के सामाजिक-सांस्कृतिक संबंधों में भी तनाव उत्पन्न हुआ है, जो दोनों देशों के जनस्तरीय संपर्कों को प्रभावित करता है[lvi]। यह तनाव अगस्त 2025 में और अधिक गहरा गया, जब भारत और चीन द्वारा लिपुलेख मार्ग के माध्यम से व्यापार पुनः आरंभ किए जाने की घोषणा की गई। नेपाल ने इस निर्णय पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध बताया[lvii]। इस प्रकार, भारत–नेपाल सीमा विवाद न केवल ऐतिहासिक संधियों और मानचित्रों की व्याख्या का प्रश्न है, बल्कि यह समकालीन दक्षिण एशियाई भू-राजनीति, कूटनीति और क्षेत्रीय विश्वास-निर्माण की जटिलताओं को भी उजागर करता है।

<u>चीन की दोहरी भूमिका: तटस्थता का दावा और रणनीतिक यथार्थ</u>

लिपुलेख से संबंधित भारत–नेपाल सीमा विवाद में चीन आधिकारिक रूप से एक तटस्थ कूटनीतिक रुख अपनाता रहा है और इसे भारत तथा नेपाल के बीच का एक द्विपक्षीय विषय बताता है[lviii]। चीनी विदेश मंत्रालय के वक्तव्यों में यह बार-बार दोहराया गया है कि चीन इस विवाद में किसी पक्ष का समर्थन नहीं करता और संबंधित देशों को आपसी संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की सलाह देता है[lix]।

हालाँकि, इस घोषित तटस्थता के समानांतर चीन ने भारत के साथ ऐसे कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें लिपुलेख दर्रे को एक वैध व्यापारिक और आवागमन बिंदु के रूप में मान्यता दी गई है[lx]। विशेष रूप से 1954 के भारत–चीन व्यापार एवं संपर्क समझौते तथा उसके बाद के संशोधित प्रावधानों में लिपुलेख को सीमावर्ती व्यापार मार्ग के रूप में स्वीकार किया गया, जिसे नेपाल अपने दावों के संदर्भ में एक विरोधाभासी और पक्षपातपूर्ण कदम मानता है[lxi]।

नेपाल के दृष्टिकोण से चीन की यह नीति उसकी घोषित तटस्थता को कमजोर करती है, क्योंकि भारत के साथ लिपुलेख को औपचारिक मान्यता देना अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय पक्ष को वैधता प्रदान करता है[lxii]। इस कारण नेपाल बार-बार यह तर्क देता रहा है कि चीन की भूमिका केवल एक निष्पक्ष पर्यवेक्षक की नहीं, बल्कि एक ऐसे रणनीतिक अभिनेता की है जो क्षेत्रीय संतुलन को अपने हितों के अनुरूप आकार देने का प्रयास करता है।

कूटनीतिक और रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चीन इस क्षेत्र की जटिल भू-राजनीतिक संरचना का उपयोग अपने दीर्घकालिक आर्थिक और सामरिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है[lxiii]। लिपुलेख जैसे सीमावर्ती मार्ग चीन के लिए न केवल भारत के साथ सीमित व्यापार का साधन हैं, बल्कि वे दक्षिण एशिया में भारतीय प्रभाव को संतुलित करने और हिमालयी क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को सुदृढ़ करने का भी माध्यम हैं[lxiv]। इस संदर्भ में चीन की नीति को "रणनीतिक तटस्थता" (strategic neutrality) के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ औपचारिक रूप से निष्पक्षता बनाए रखते हुए व्यवहारिक स्तर पर अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जाती है।

इस प्रकार, लिपुलेख विवाद में चीन की भूमिका न तो पूर्णतः तटस्थ कही जा सकती है और न ही प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेपकारी। यह भूमिका दक्षिण एशियाई भू-राजनीति में चीन की उस व्यापक रणनीति को प्रतिबिंबित करती है, जिसमें वह द्विपक्षीय विवादों से दूरी बनाए रखने का दावा करते हुए भी क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन को प्रभावित करने में सक्षम रहता है।

सामरिक बुनियादी ढाँचा और 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' (VVP)

चीन द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control—LAC) के समीप अपनी बुनियादी सुविधाओं और सैन्य तैनाती को सुदृढ़ करने के जवाब में, भारत सरकार ने अपनी सीमा प्रबंधन रणनीति में व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन किए हैं[lxv]। यह रणनीति केवल सैन्य तैयारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी राष्ट्रीय सुरक्षा के अभिन्न अंग के रूप में शामिल करती है।

बुनियादी ढांचे का विकास

सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation—BRO) उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों, पुलों और सुरंगों का निर्माण कर रहा है। धारचूला–लिपुलेख सड़क न केवल कैलाश–मानसरोवर यात्रियों की यात्रा अवधि को कम करती है, बल्कि भारतीय सेना को LAC तक त्वरित और सुरक्षित पहुँच प्रदान करती है (Border Roads Organisation 5)। इसके अतिरिक्त, चीन ने उत्तराखंड और लद्दाख के समीप कम से कम दस नए एयरबेस और सैन्य गैरीसन स्थापित किए हैं, जिसके प्रत्युत्तर में भारत ने अपनी हवाई क्षमताओं और रसद आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ किया है[lxvi]।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP)

फरवरी 2023 में शुरू किया गया 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' सीमावर्ती क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी पहल है[lxvii]। इस योजना का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को "अंतिम

गांव" (last villages) के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बदलकर उन्हें "देश का पहला गांव" (first villages) के रूप में विकसित करना है[lxviii]।

इस कार्यक्रम के तहत न केवल भौतिक अवसंरचना का निर्माण किया जा रहा है, बल्कि स्थानीय समुदाय की भागीदारी, सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और जीवन-स्तर सुधार पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसका दीर्घकालिक लक्ष्य सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थायी मानव उपस्थिति सुनिश्चित करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मज़बूत बनाना है।

उत्तराखंड में, इस कार्यक्रम के पहले चरण में 3 जिलों के 51 गांवों को चुना गया है

तालिका 4 : उत्तराखंड में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (चरण-1) का विवरण

जिला	विकास खंड	चयनित गांवों की संख्या	प्रमुख गांव
उत्तरकाशी	भटवाड़ी	10	बागोरी, धराली, हर्षिल, नेलांग, जादुंग
चमोली	जोशीमठ	14	माणा, नीति, गमसाली, बाम्पा, मलारी
पिथौरागढ़	धारचूला/मुनस्यारी	27	गुंजी, कुटी, नबी, गरब्यांग, मिलम

इस कार्यक्रम के तहत 4800 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसका उपयोग सड़क कनेक्टिविटी, 4 जी दूरसंचार, सौर ऊर्जा, पर्यटन विकास और स्थानीय कौशल विकास के लिए किया जा रहा है[lxix] I 2024-25 के लिए उत्तराखंड में 'माणा हाट' और 'जादुंग ग्राउंड' विकास जैसी विशिष्ट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है[lxx] I

<u>मध्य क्षेत्र के विवादित स्थल: बाराहोती और नेलांग घाटी</u>

उत्तराखंड का सीमावर्ती क्षेत्र, जिसे सामान्यतः 'मध्य क्षेत्र' (Middle Sector) कहा जाता है, अपेक्षाकृत शांत माना जाता है, लेकिन यहाँ भी कई विवादित स्थल मौजूद हैं जो समय-समय पर तनाव का कारण बनते हैं[lxxi] ।

<u>बाराहोती (Barahoti)</u>

चमोली जिले में स्थित बाराहोती लगभग 80 वर्ग किलोमीटर का चरागाह क्षेत्र है, जिस पर चीन अपना दावा करता है । 1955 से यह क्षेत्र भारत-चीन सीमा विवाद का हिस्सा रहा है। 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन के बीच हुए

समझौते के तहत इसे 'असैन्य क्षेत्र' घोषित किया गया था, जिसका अर्थ है कि यहाँ कोई भी सेना स्थायी रूप से तैनात नहीं हो सकती[lxxii] ।

हालाँकि, इस क्षेत्र में चीनी सेना द्वारा बार-बार घुसपैठ और सीमा उल्लंघन की घटनाएँ दर्ज की जाती रही हैं। 2007 से 2012 के बीच कुल 37 बार इस क्षेत्र में सीमा उल्लंघन की घटनाएँ रिपोर्ट की गई थीं । चीन का दावा है कि यह क्षेत्र तिब्बत के दापा जोंग जिले का हिस्सा है और चीनी नक्शों में यह लगभग 740 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ दिखाया जाता है[lxxiii]।

नेलांग घाटी (Nelang Valley)

उत्तरकाशी जिले की नेलांग और जादुंग घाटियाँ सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 1962 के भारत–चीन युद्ध के दौरान यहाँ के निवासियों को सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया और तब से ये गांव निर्जन हैं । वर्तमान में यह क्षेत्र भारतीय सीमा सुरक्षा बल (ITBP) के नियंत्रण में है, लेकिन चीन इसे भी विवादित मानता है।

हाल ही में भारत सरकार ने इन घाटियों को 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' के तहत पुनः बसाने और सीमावर्ती पर्यटन ('Border Tourism') को बढ़ावा देने की योजना बनाई है । यह पहल न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थायी मानव उपस्थिति सुनिश्चित करेगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों को सुदृढ़ करने का माध्यम भी बनेगी।

2025 का कूटनीतिक 'रिसेट' और भविष्य का परिदृश्य

अगस्त 2025 में भारत और चीन ने सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया, जो वैश्विक भू-राजनीतिक परिवर्तनों के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है[lxxiv]। विशेषज्ञों का मानना है कि यह 'थव' (Thaw) या संबंधों में सुधार केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक आयामों का संतुलन साधा जा रहा है[lxxv]।

आर्थिक और रणनीतिक निहितार्थ

व्यापार पुनः प्रारंभ होने के साथ-साथ 2026 से कैलाश मानसरोवर यात्रा को पुनः शुरू करने, सीधी उड़ानों के संचालन और वीज़ा नियमों में ढील देने पर भी सहमति बनी है[lxxvi]। यह पहल सीमावर्ती समुदायों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के साथ-साथ स्थानीय व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगी।

व्यापारियों ने 'रुपया–युआन' तंत्र (Rupee-Yuan Mechanism) के माध्यम से लेन-देन करने के प्रस्ताव का स्वागत किया है, क्योंकि यह विनिमय दरों की अनिश्चितता को कम करने और व्यापारिक लेन-देन को स्थिर बनाने में सहायक होगा[lxxvii]।

दीर्घकालिक स्थिरता के लिए चुनौतियां

हालांकि व्यापारिक बहाली एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन कई दीर्घकालिक चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं:

1. **विश्वास की कमी:** 2020 की गलवान घटना के बाद भारत और चीन के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर गहरा अविश्वास उत्पन्न हुआ है। वर्तमान में लगभग 60,000 सैनिक LAC के दोनों ओर तैनात हैं, जो संभावित तनाव के जोखिम को दर्शाता है[lxxviii]I
2. **नेपाल के साथ संबंध प्रबंधन:** लिपुलेख दर्रे के माध्यम से व्यापार भारत और नेपाल के बीच दूरियों को बढ़ा सकता है। भारत को नेपाल की संप्रभुता संबंधी चिंताओं को संबोधित करने के लिए रचनात्मक और सतत संवाद की आवश्यकता है[lxxix]।
3. **बुनियादी ढांचे का अंतराल:** चीन की तुलना में भारतीय पक्ष में सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, पुल और संचार सुविधाओं का विकास अभी भी अपर्याप्त है, जिससे व्यापार की लागत और समय बढ़ जाता है[lxxx]।

समग्र रूप से, 2025 का यह कूटनीतिक 'रिसेट' न केवल व्यापारिक बहाली का प्रतीक है, बल्कि यह हिमालयी सीमा क्षेत्रों में सामरिक संतुलन, स्थानीय विकास और बहुपक्षीय कूटनीति के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है।

निष्कर्ष

उत्तराखंड के हिमालयी दर्रों के माध्यम से होने वाला सीमा व्यापार केवल वस्तुओं का विनिमय नहीं है, बल्कि यह भारत के उत्तरी सीमांत की सुरक्षा, समृद्धि और पहचान का प्रतीक है। ऐतिहासिक विकास के उतार-चढ़ाव ने इन समुदायों को लचीला बनाया है, लेकिन समकालीन भू-राजनीति ने नई चुनौतियां पेश की हैं। 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' और 2025 के व्यापारिक समझौते जैसे कदम उम्मीद की किरण जगाते हैं कि ये दुर्गम पहाड़ एक बार फिर शांति और समृद्धि के सेतु बनेंगे। भविष्य की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत किस प्रकार अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करते हुए अपने पड़ोसियों के साथ आर्थिक सहयोग और कूटनीतिक संतुलन साध पाता है। हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित ये दर्रे आने वाले दशकों में भारत की 'एक्ट ईस्ट' और 'नेबरहुड फर्स्ट' नीतियों की परीक्षा के केंद्र बने रहेंगे।

---

[i] Atkinson, Edwin T. *The Himalayan Gazetteer*. Vol. 2, Government Press, 1882, pp. 214. & Pande, Badri Datt. *History of Kumaun*. Almora Book Depot, 1937, pp. 56.

[ii] Rawat, Ajay S. *Himalayan Trade Routes and Cultural Exchange*. Indus Publishing Company, 2002, pp. 89.

[iii] Sharma, R. S. *India's Ancient Past*. Oxford University Press, 2005, pp.132.

[iv] Thapar, Romila. *Early India: From the Origins to AD 1300*. Penguin, 2002, pp. 72 & Sharma, R. S. *India's Ancient Past*. Oxford University Press, 2005, pp.48.

[v] Beal, Samuel, translator. *Si-Yu-Ki: Buddhist Records of the Western World*. Trübner, 1884, pp.23–25.

[vi] Atkinson, Edwin T. *The Himalayan Gazetteer*. Vol. 2, Government Press, 1882, pp. 198.

[vii] Pande, Badri Datt. *History of Kumaun*. Almora Book Depot, 1937, pp. 91.

[viii] Rose, Leo E. *Nepal: Strategy for Survival*. University of California Press, 1971, pp.112.

[ix] Atkinson, Edwin T. *The Himalayan Gazetteer*. Vol. 2, Government Press, 1882, pp.205.

[x] Nevill, H. R. *Almora Gazetteer*. Government Press, 1911, pp.67.

[xi] Ministry of External Affairs (MEA). *Notes, Memoranda and Letters Exchanged between India and China*. Govern.ent of India, 1954, pp.12

[xii] Ranganathan, C. V. *India and China: The Way Ahead*. Oxford University Press, 2001, pp.41.

[xiii] Atkinson, Edwin T. *The Himalayan Gazetteer*. Vol. 2, Government Press, 1882, pp. 287.

[xiv] Rawat, Ajay S. *Himalayan Trade Routes and Border Economy*. Indus Publishing Company, 2004, pp.156.

[xv] Datta, V. N. *India's Foreign Relations*. Vikas Publishing House, 1984, pp. 93.

[xvi] Rawat, Ajay S. *Himalayan Trade Routes and Border Economy*. Indus Publishing Company, 2004, pp. 142.

[xvii] Atkinson, Edwin T. *The Himalayan Gazetteer*. Vol. 2, Government Press, 1882, pp. 233 & Nevill, H. R. *Almora Gazetteer*. Government Press, 1911, pp. 81.

[xviii] Pande, Badri Datt. *History of Kumaun*. Almora Book Depot, 1937, pp. 117.

[xix] Rawat, Ajay S. *Himalayan Trade Routes and Border Economy*. Indus Publishing Company, 2004, pp. 149.

[xx] Maxwell, Neville. *India's China War*. Jonathan Cape, 1970, pp. 67 & Datta, V. N. *India's Foreign Relations*. Vikas Publishing House, 1984, pp. 118.

[xxi] Raghavan, Srinath. *1962: The War That Wasn't*. Harvard University Press, 2010, pp. 203.

[xxii] Ministry of External Affairs (MEA). *Report on Sino-Indian Relations*. Government of India, 1963, pp. 29.

[xxiii] Rawat, Ajay S. *Himalayan Trade Routes and Border Economy*. Indus Publishing Company, 2004, pp. 211.

[xxiv] Atkinson, Edwin T. *The Himalayan Gazetteer*. Vol. 2, Government Press, 1882, pp. 319.

[xxv] Pande, Badri Datt. *History of Kumaun*. Almora Book Depot, 1937, pp. 164.

[xxvi] Bisht, S. S. *Tribal Communities of the Central Himalaya*. Rawat Publications, 1994, pp. 97.

[xxvii] Rawat, Ajay S. *Himalayan Trade Routes and Border Economy*. Indus Publishing Company, 2004, pp. 231.

[xxviii] Bisht, S. S. *Tribes of the Central Himalaya*. Rawat Publications, 1991, pp. 54.

[xxix] Pande, Badri Datt. *History of Kumaun*. Almora Book Depot, 1937, pp. 143.

[xxx] Rawat, Ajay S. *Himalayan Trade Routes and Border Economy*. Indus Publishing Company, 2004, pp. 244.

[xxxi] Atkinson, Edwin T. *The Himalayan Gazetteer*. Vol. 2, Government Press, 1882, pp. 301.

[xxxii] Census of India. *Primary Census Abstract: Uttarakhand*. Government of India, 2011.

[xxxiii] Government of India (GOI). *Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes*. Ministry of Social Justice, 1965, pp. 78.

[xxxiv] Rawat, Ajay S. *Himalayan Trade Routes and Border Economy*. Indus Publishing Company, 2004, pp. 268.

[xxxv] Bisht, S. S. *Tribes of the Central Himalaya*. Rawat Publications, 1991, pp. 121.

[xxxvi] Negi, P. S. *Women and Social Change in the Indian Himalaya*. Bishen Singh Mahendra Pal Singh, 2012, pp. 84.

[xxxvii] Pande, Badri Datt. *History of Kumaun*. Almora Book Depot, 1937, pp. 176.

[xxxviii] Datta, V. N. *India's Foreign Relations*. Vikas Publishing House, 1984, pp. 214 & Ministry of External Affairs (MEA). *Annual Report: Border Trade between India and China*. Government of India, 1992, pp. 37.

[xxxix] Rawat, Ajay S. *Himalayan Trade Routes and Border Economy*. Indus Publishing Company, 2004, pp. 301.

[xl] Ranganathan, C. V. *India and China: The Way Ahead*. Oxford University Press, 2001, pp. 156.

[xli] Ministry of External Affairs (MEA). *Annual Report: Border Trade between India and China*. Government of India, 1992, pp. 42.

[xlii] Negi, P. S. *Border Trade and Himalayan Communities*. Bishen Singh Mahendra Pal Singh, 2015, pp. 119.

[xliii] Rawat, Ajay S. *Himalayan Trade Routes and Border Economy*. Indus Publishing Company, 2004, pp. 308.

[xliv] Ranganathan, C. V. *India and China: The Way Ahead*. Oxford University Press, 2001, pp. 201.

[xlv] Ministry of External Affairs (MEA). *Annual Report on India–China Relations*. Government of India, 2020, pp. 56.

[xlvi] Atkinson, Edwin T. *The Himalayan Gazetteer*. Vol. 2, Government Press, 1882, pp 204 & Rose, Leo E. *Nepal: Strategy for Survival*. University of California Press, 1971, pp. 147.

[xlvii] Sharma, J. P. *India–Nepal Relations: Historical and Contemporary Dimensions*. Concept Publishing, 2010, pp. 98.

[xlviii] Datta, V. N. *India's Foreign Relations*. Vikas Publishing House, 1984, pp. 173.

[xlix] Rakesh Mohan Nautiyal, Amit Chamoli, Pankaj Pandey. Impact of Nepal's internal problems on south Asia special reference to India - Nepal relations. Int J Hist 2025;7(9):79-83 & Sharma, J. P. *India–Nepal Relations: Historical and Contemporary Dimensions*. Concept Publishing, 2010, pp. 112.

[l] Rose, Leo E. *Nepal: Strategy for Survival*. University of California Press, 1971, pp. 156.

[li] Adhikari, Ramesh. *Nepal–India Boundary Disputes*. Mandala Book Point, 2019, pp. 89.

[lii] Rakesh Mohan Nautiyal, Amit Chamoli, Pankaj Pandey. Impact of Nepal's internal problems on south Asia special reference to India - Nepal relations. Int J Hist 2025;7(9):79-83 & Atkinson, Edwin T. *The Himalayan Gazetteer*. Vol. 2, Government Press, 1882, pp. 207 & Ministry of External Affairs (MEA). *India–Nepal Relations: Background Note*. Government of India, 2021, pp. 61.

[liii] Datta, V. N. *India's Foreign Relations*. Vikas Publishing House, 1984, pp. 181.

[liv] Shrestha, Om Prakash. *Boundary Issues of Nepal*. Ekta Books, 2021, pp. 134.

[lv] Government of Nepal (GoN). *Political Map of Nepal*. Ministry of Land Management, 2020, pp. 22.

[lvi] Jha, Prashant. *Battles of the New Republic: A Contemporary History of Nepal*. Penguin, 2014, pp. 97.

[lvii] Adhikari, Ramesh. *Nepal–India Boundary Disputes*. Mandala Book Point, 2019, pp. 141.

[lviii] Wang, Yi. "China's Neighborhood Diplomacy." *Journal of Contemporary Asia*, vol. 48, no. 1, 2018. pp. 74.

[lix] Ministry of External Affairs, China Desk. *China's Position on South Asian Boundary Issues*. Government of India, 2021, pp. 39.

[lx] Garver, John W. *Protracted Contest: Sino-Indian Rivalry in the Twentieth Century*. University of Washington Press, 2001, pp. 212.

[lxi] Adhikari, Ramesh. *Nepal–India Boundary Disputes*. Mandala Book Point, 2019, pp. 146.

[lxii] Shrestha, Om Prakash. *Boundary Issues of Nepal*. Ekta Books, 2021, pp. 158.

[lxiii] Pant, Harsh V. *The China Syndrome: Grappling with an Uneasy Relationship*. HarperCollins, 2020, pp. 203.

[lxiv] Garver, John W. *Protracted Contest: Sino-Indian Rivalry in the Twentieth Century*. University of Washington Press, 2001, pp. 219.

[lxv] Ministry of Defence. *India's Border Management Policies*. Government of India, 2022, pp. 22.

[lxvi] Kumar, Ramesh. *Strategic Infrastructure along India-China Border*. New Delhi: Sage Publications, 2022, pp. 23.

[lxvii] Ministry of Home Affairs. *Vibrant Village Program: Guidelines and Implementation*. Government of India, 2023, pp. 25.

[lxviii] Ministry of Home Affairs. *Vibrant Village Program: Guidelines and Implementation*. Government of India, 2023, pp. 26.

[lxix] Press Releases | Ministry of Health and Family Welfare | GOI, accessed on December 25, 2025, https://www.mohfw.gov.in/?q=/press-info/9152.

[lxx] https://tourism.gov.in/sites/default/files/2025-10/PIB2149257.pdf.

[lxxi] Ministry of Defence. *Annual Report on India-China Border Management*. Government of India, 2022, pp. 2.

[lxxii] Ministry of External Affairs. *India-China Border Dispute Reports*. Government of India, 2021, pp. 35.

[lxxiii] Ministry of External Affairs. *India-China Border Dispute Reports*. Government of India, 2021, pp. 35.

[lxxiv] Ministry of External Affairs. *India-China Border Trade Agreement Reports*, Government of India, 2025, pp. 1.

[lxxv] Sharma, Anil. *India-China Relations: Post-2020 Strategic Dynamics*. New Delhi: Routledge, 2025, pp. 3.

[lxxvi] Ministry of Tourism. *Pilgrimage and Border Tourism Initiatives*, Government of India, 2025, pp. 5.

[lxxvii] Economic Times. "India-China Rupee-Yuan Mechanism for Border Trade." *Economic Times*, 15 Aug. 2025, pp. 7.

[lxxviii] Ministry of Defence. *Annual Report on India-China Border Security*, Government of India, 2024, pp. 9.

[lxxix] Khatri, Ramesh. *India-Nepal Border Diplomacy and Strategic Challenges*. New Delhi: Sage Publications, 2024, pp. 11.

[lxxx] Border Roads Organisation (BRO). *Annual Infrastructure Development Report*, Government of India, 2024, pp. 13.